यह काम करने के लिए दिया गया और तजुर्बे के तौर पर उनको यह काम करने के लिए दिया गया था। लेकिन मकान बनाने में ये तजुर्बा फेल हुआ हैं।

श्री नवाब सिंह चौहान : जब कि अधिक से अधिक सवा ६ लाख रु० के खर्च का तखमीना किया गया था, तो फिर १२ लाख रु० उनको क्यों दिया गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह मामला पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने आया हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया हैं। यह १९४९ की बात हैं जब ये सारी बातें वहां उठाई गई थीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था और वे एक नया तरीका चलाना चाहते थे। मगर इस नये तरीके से जो उम्मीद की गई थी, वह पूरी नहीं हुई।

श्री नवाब सिंह चौहान : जैसा कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया हैं कि इसकी जांच जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० ने की थी उस ने अपनी रिपोर्ट में कहा हैं कि यह जो १२ लाख रु० दिया गया हैं यह बिलकुल उससे दुगुनी रकम हैं जितनी कि दी जानी चाहिए थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह: इस बात में शक नहीं हैं कि सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० ने उस वक्त भी यह राय, यह सलाह, दी थी कि यह जो नया तरीका हैं उसके कामयाब होने की उम्मीद नहीं हैं और जो रीमा कंस्ट्रक्शन कम्पनी क्लेम करती हैं उसके मुकाबले खर्चा भी उससे ज्यादा ही होगा। फिर भी एक हाई लेवल पर दो, तीन मिनिस्टर साहबान ने बैठकर इस बात का फैसला किया। आखिर जो सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० की राय थी वह बाद के तजुर्बे से ठीक साबित हुई।

डा० रघुबीर सिंह : वे मिनिस्टर कौन थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह: १९४९ की बात हैं। उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और कोई दूसरे मिनिस्टर थे।

श्री नवाब सिंह चौहान : इन ब्लाक्स के बनने में कितना वक्त लगा ? सन् १९४९ में शुरू हुआ तो कौन से सन् में किस वक्त पूरा हुआ ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मेरा खयाल हैं यह १९५१ या १९५२ में खत्म हुआ।

श्री कन्हैयालाल दा० वैद्य : क्या ये बने हुए ब्लाक्स अस्पताल के काम में आ रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह: जी हां, काम तो आ रहे हैं, मगर इनका काम तसल्लीबख्श नहीं हैं।

PROF. G. RANGA: When was this contract made with this firm? Was it after they had knowledge of the failure of the shops produced by the pre-fab factory and after the failure of the Housing Scheme?

सरदार स्वर्ण सिंह: नहीं, नहीं। यह तो उससे पहले की बात हैं, १९४९ की।

नरेला स्थित मकानों का विस्थापितों को किराये पर दिया जाना

***१९९. श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष नरेला स्थित जो १६० मकान केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने यहां की राज्य सरकार को विस्थापितों के उपयोग के लिये दिये थे उन में से कितने किराये पर उठ गये हैं;

(ख) ऐसे मकानों की संख्या कितनी हैं जो अभी भी खाली पड़े हैं और उन के खाली रहने का कारण क्या हैं तथा इन मकानों की

लागत क्या हैं और इन से वार्षिक किराया कितना आता हैं; और

(ग) क्या वहां पर बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क व यातायात आदि की सुविधायें हैं ?

t [RENTING OUT OF HOUSES TO DISPLACED PERSONS AT NARELA

•181. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of houses let out, of the 190 houses at Narela handed over last year to the Delhi State Government by the Central Rehabilitation Ministry for the use of displaced persons;

(b) the number of such houses still lying vacant and the reasons therefor, the cost of those houses and their total annual rent; and

(c) whether such facilities as electricity, water supply, medical treatment, education, roads, transport etc. exist there?]

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) कोई नहीं । २०० मकानों में से १९८ मकान दिल्ली राज्य सरकार को, पिछले साल में नहीं, बल्कि इस साल में दिये गये थे ।

(ख) १९८ । नरेला में सड़कों पर बसे हुए लोग इतने गरीब हैं कि वे उन मकानों का किराया नहीं दे सकते जो खाली पड़े हुए हैं । इसलिये किराये की वसूली का सवाल नहीं उठता । इन मकानों की कुल लागत ३,६५,१६६ रुपये हैं ।

(ग) सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने गलियों में रोशनी लगाने का जितना खर्च बताया हैं उस पर अभी विचार किया जा रहा हैं । पानी के लिये हाथ पम्प हैं । नरेला में जो स्कूल और अस्पताल हैं, उनके अलावा और कोई विशेष प्रबन्ध पढ़ाई व इलाज के लिए नहीं किया गया हैं । गन्दे और बरसाती पानी निकालने की नालियां बनाई जा चुकी हैं । ये मकान सड़क के किनारे पर बने हुए हैं इसलिये रेल और सड़क से आने जाने के साधन मौजूद हैं । अन्दर की सड़क बनाने का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला हैं और आशा हैं कि यह काम ३१ मार्च १९५६ तक पूरा हो जायगा ।

I [THE DEPUTY MINISTER FOR REHABILITATION (SHRI J. K. BHONSLE): (a) Nil. Out *oi* 200 houses, 198 houses were handed over to the Delhi State Government, in the middle of the current year, and not during last year.

(b) 198. The squatters at Narela are too poor to afford the rents of these tenements lying vacant. The question of rent realization, therefore, does not arise. The total cost of these houses is Rs. 3.65,166.

(c) Estimates submitted by the Central Public Works Department for street lighting in the colony are being examined. Water is supplied through hand pumps. No separate arrangements for medical ca¥e or education, other than those existing in the town itself, have been made for the colony. Internal sullage and storm water drains have been completed. The colony is situated on a main road and as such both rail and road conveyance are available. The construction of internal roads is being taken up shortly and is expected to be completed by 31st March 1956.]

श्री नवाब सिंह चौहान : इन क्वार्टर्स को केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को किन खास शर्तों पर दिया था ?

श्री जे० के० भोंसले : हमने ये मकान खास नरेला के लोगों के लिए बनाए थे । हमने इन मकानों को सेंट्रल पी० डब्लू० डी० की तरफ से बनवा कर उनको दिल्ली स्टेट गवर्नमेन्ट के सिपुर्द कर दिया था ताकि वह उन को एलाट करें ।

t English translation.

श्री नवाब सिंह चौहान : जो मकान किसी को एलाट नहीं हैं और खाली पड़े हुए हैं उन के लिए सरकार भविष्य में क्या सोच रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह तो मैंने बतला दिया है कि नरेला के लोग इतने गरीब हैं कि वे इन मकानों में नहीं जा सकते । तो इसलिए हम उनको ऑक्शन करेंगे ।

श्री नवाब सिंह चौहान : अगर मकान खाली पड़े हुए हैं और वे लोग इतने गरीब हैं कि किराया नहीं दे सकते हैं तो क्या सरकार सोच रही है कि उनको मुफ्त में, बगैर किराये के, ये मकान रहने के लिये दे दिये जाएं ?

श्री जे० के० भोंसले : अगर सरकार या पार्लियामेंट के मेम्बर देना चाहते हैं, तो हम "नहीं" नहीं बोलते ।

श्री नवाब सिंह चौहान : किराये का सवाल है, मिल्कियत का सवाल नहीं है । अगर वह किराये पर नहीं उठते तो क्या सरकार उन्हें फरोख्त करेगी ? या कि उन्हें खाली रखने का ही इरादा है ?

श्री जे० के० भोंसले : खाली तो पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जगह की बहुत कमी है और ऑक्शन करने से बहुत लोग लेंगे । साथ ही साथ मुझे यह भी मालूम है कि नरेला में जो लोग रहते हैं उन्होंने दूसरों के साथ रहने का इंतजाम किया है और शायद वे मकान नहीं मांगते ।

श्री कन्हैयालाल डी० वैद्य : क्या यह बात सही है कि ये मकान इतने नीचे हैं कि जाड़ों में इतने सर्द और गर्मियों में इतने गर्म पड़ जाते हैं कि रहना मुश्किल हो जाता है ?

श्री जे० के० भोंसले : देहली ऐसा शहर है कि सर्दी के मौसम में ज्यादा सर्द और गरमी के मौसम में ज्यादा गर्म हमेशा रहता है ।

SHRI RATANLAL KISHORILAL MALVIYA: Is it a fact that these houses that have been put to auction fetch much more value than the cost of construction and are purchased by the richer refugees who purchase the claims of the other people at low cost? If so, will Government think over this matter and put a stop to these auctions and make allotment to the people concerned?

SHRI M. C. KHANNA: May r make a submission at this stage? I answered this very question only about four days ago when it was raised by the hon. Member sitting opposite. I explained the position about the sale and the auction at length to this House.

सरकार के कर्मचारियों और विभागों से बकाया किराये की वसूली

***१८२. श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी इमारतों का कुल कितना किराया बाकी है;

(ख) क्या किन्हीं मंत्रालयों या सरकारी मुहकमों पर भी कुछ किराया बाकी है;

(ग) इस किराये के बाकी रहने का कारण क्या है; और

(घ) सरकार ने कितना किराया बट्टे खाते में डाल दिया है और क्यों ?

t [RECOVERY OF OUTSTANDING RENT FROM GOVERNMENT EMPLOYEES AND DEPARTMENTS

*182. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for WORKS. HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the total amount outstanding up to date from Government

fEnglish translation.